भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1521
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

त्रिपुरा में शीत श्रृंखला योजना

1521. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि छोटे किसानों और छोटे संगठनों विशेष रूप से दूरस्थ अथवा अल्पविकसित क्षेत्रों, खासकर त्रिपुरा राज्य में इस योजना के लाभों से अवगत हों और उन्हें इसका लाभ मिल सके;
- (ख) क्या सरकार का शीत श्रृंखला योजना का मौजूदा अवसंरचना से इतर विस्तार करने का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधान मंत्री किसान योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक 'एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना' योजना के अंतर्गत समय-समय पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके त्रिपुरा राज्य सहित देश भर से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। उपर्युक्त योजना के व्यापक प्रचार के लिए, इसे प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, दिशानिर्देश और अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्रासंगिक संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान की जाती है। छोटे किसानों के साथ-साथ संस्थाएं/संगठन जैसे एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियां आदि सहित व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रचारात्मक गतिविधियों की योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने वर्ष 2024 के दौरान देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे 60 कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि शीत श्रृंखला योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

(ख) और (ग): शीत श्रृंखला योजना जारी है और यह मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पूरे देश से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।